भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4821

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में अमृत 2.0

4821. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी), बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए) या कर्नाटक राज्य सरकार ने आरआर नगर और कोनानाकुंटे जैसे क्षेत्रों में अमृत 2.0 के अंतर्गत जंक्शन सुधार, सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन या फ्लाईओवर कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा शहरी परिवहन घटक के अंतर्गत कोई धनराशि स्वीकृत की गई है या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है. और
(ग) क्या सरकार का बीबीएमपी परिधीय क्षेत्रों के लिए व्यापक आवागमन योजना को सहयोग करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के उद्देश्य से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू की गई है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित स्थलों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि अमृत 2.0 दिशानिर्देशों में जंक्शन सुधार, सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन और फ्लाईओवर निर्माण कार्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य द्वारा अमृत 2.0 के तहत इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगलौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण (यूटीपीसीबी) योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक -II में दिया गया है।

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान मंत्रालय को बीबीएमपी परिधीय क्षेत्रों के लिए व्यापक मोबिलिटी योजना (सीएमपी) के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने शहरी भूमि परिवहन निदेशालय (डीयूएलटी) द्वारा तैयार की गई व्यापक मोबिलिटी योजना (सीएमपी) अनुमोदित की है, जिसमें 2035 तक की योजना अवधि के साथ सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित बीबीएमपी परिधीय क्षेत्रों के लिए कार्यनीतियाँ शामिल हैं।

" कर्नाटक में अमृत 2.0 " के संबंध में दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4821 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंगलोर मेट्रो के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	**मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम**	**2022-23 के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधियां**	**2023-24 के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधियां**	**2024-25 के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधियां**
1.	बैंगलोर मेट्रो (बीएमआरसीएल)	4,041.61	3,617.16	4,814.58

"कर्नाटक में अमृत 2.0 " के संबंध में दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4821 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण (यूटीपीसीबी) योजना के अंतर्गत जारी निधियों का विवरण

क्र.सं.	अध्ययन का नाम	वर्ष	अध्ययन की कुल लागत (रुपये में)	भारत सरकार का हिस्सा (रुपए में)	आज तक जारी की गई धनराशि (रुपये में)
1.	निम्नलिखित मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करना: (i) 42 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो रेल परियोजना जिसमें दो कॉरिडर शामिल हैं (क) जेपी नगर से हेब्बल का चौथा चरण (ओआरआर पश्चिम के साथ) (ख) होसाहल्ली से कडाबागेरे (मगदी रोड के साथ) (ii) सरजापुर से हेब्बल तक 37 किलोमीटर तक मेट्रो रेल परियोजना	2022	450.88 लाख (जीएसटी सहित)	225.44 लाख (जीएसटी सहित)	88.694 लाख
2.	कर्नाटक के मैसूर शहर के लिए सीएमपी की तैयारी	2024	61,13,804 (जीएसटी सहित)	61,13,804 (जीएसटी सहित)	12,22,761